आकाशवाणी शिमला

28.08.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945 बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर हिमाचल के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का लगाया आरोप।
- राज्य सरकार अगले 9 महीनों में करूणामूलक आधार पर सभी आश्रितों को देगी नौकरी–एक हजार 4 सौ 15 मामले लम्बित।
- प्रदेश में वनों के अवैध कटान के मामलों पर सख्ती से निपटेगी सरकार–दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गैंगवार, नशे की तस्करी और मॉब लिचिंग को सामान्य बात मानने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार जलविद्युत और अन्य परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने राज्य के हितों के खिलाफ धौलासिद्ध, लूहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस सरकार ने राज्य के हित में अपने स्वयं के संसाधनों से बल्क ड्रग परियोजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व, विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क के लिए पूरी तरह से गंभीर है और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर इस प्रोजेक्ट के लिए एक हजार करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क का 30 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को जल्द वापस करेगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और इससे 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है और इसके लिए राज्य सरकार ने भी 50 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। उद्योग मंत्री ने विधायक सतपाल सत्ती के अनुपूरक सवाल के जवाब में कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को आएगा। प्रोजेक्ट के काम के लिए टेंडर की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के उत्तर में कहा कि राज्य सरकार अगले नौ महीनों में करुणामूलक आधार पर सभी आश्रितों को नौकरी उपलब्ध करवा देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के एक हजार 4 सौ 15 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने 20 माह के कार्यकाल में अभी तक एक सौ 80 लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए पात्र लोगों को चतुर्थ श्रेणी के अलावा तृतीय श्रेणी की नौकरियां देने पर भी विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जो अगले छह माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के एक सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग बाजार में चौल–जंजैहली सड़क पर रोपड़ी खड्ड पर पुल का शेष कार्य बजट का प्रावधान होने पर पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगी। विधायक विपिन परमार की अनुपस्थिति में उनकी ओर से अधिकृत विधायक राकेश जम्वाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और अध्यापकों की संख्या ज्यादा है वहां पर युक्तिकरण करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विधायकों से भी सहयोग मांगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में सांपों के काटने से होने वाली मौतों के मामले में संबंधित परिजनों को मुआवजा देने विचार करेगी। इसके लिए सरकार राहत मैनुअल में आवश्यक संशोधन करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दखल देते हुए की। उन्होंने राजस्व मंत्री से इस संबंध में आवश्यक अध्ययन करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के दिनों में खड्डों और नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में स्नेक बाईट की ज्यादा घटनाएं होती हैं। इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में कहा कि सांप के काटने पर अब लोगों को तत्काल इलाज मिलेगा। इसके लिए सीएचसी और पीएचसी स्तर पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ ही हर 108 एंबुलेंस में भी एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन रखे जाएंगे।

अवैध कटान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार वनों के अवैध कटान से सख्ती से निपटेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सराज वन मण्डल के बंजार में सुराग शिल्ह जंगल में काटे गए हरे पेड़ों के अवैध कटान के मामले में आरोपी ठेकेदार पर 99 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो जांच हुई है, उसमें 16 पेड़ अवैध रूप से काटने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में और तथ्य आएंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वे आज विधानसभा में विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा नियम–62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुराग शिल्ह जंगल में 8 सौ 36 सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। इसमें से 3 सौ 58 पेड़ काटे जा चुके हैं। उन्होंने विधायक सुरेंद्र शौरी के उस दावे को खारिज कर दिया कि ठेकेदार ने चार सौ से अधिक पेड़ अनधिकृत रूप से काट दिए हैं। इस संबंध में बंजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में गैंगवार, नशे की तस्करी और मॉब लिचिंग को सामान्य घटना मानने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न तरह के माफिया लगातार बढ़ रहा है और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सचिवालय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर उन्हें खामोश करना चाहती है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सिर्फ झूठ के सहारे सरकार चलाने और लोगों को मुद्दों से गुमराह न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने करीब 5 हजार करूणामूलकों को नौकरियां दी थी जबकि कांग्रेस सरकार ने दो साल में केवल एक सौ 80 लोगों को ही नौकरी दी है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हेलीपोर्ट्स और होटलों सहित पर्यटन की अन्य परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में आज पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सभी हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन विभाग को कांगड़ा जिला के पालमपुर में कम से कम पांच हजार लोगों की क्षमता वाले सम्मेलन कक्ष निर्मित करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और राज्य पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस बाली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।

पैनडाउन स्ट्राइक

आई.जी.एम.सी. शिमला अस्पताल के आर. के. एस. कर्मचारी रैगुलर पे स्केल की मांग को लेकर 27 से 31 अगस्त तक सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक पैनडाऊन स्ट्राइक पर चले गए हैं। आर.के.एस.कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद पाल ने कहा कि 31 अगस्त तक मांग नहीं मानी गई तो कर्मचारी 2 सितंबर से पूरे दिन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आई.जी.एम.सी. मे 2016 में 36 आर.के.एस कर्मचारियों को और उसके बाद 2019 में एक कर्मचारी को रेगुलर पे स्केल सरकार की नोटीफिकेशन के आधार पर दिया जा चुका है लेकिन 2021 में आर के एस के तहत 55 कर्मचारी आठ साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं मगर सरकार रेगुलर पे स्केल नहीं दे रही है।

दुर्घटना

चंबा जिला के भरमौर भरमाणी सड़क मार्ग पर आज सुबह मणिमहेश यात्रा के दौरान एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि दस व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों में चार की हालत गंभीर है, जिन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज और अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरमौर में भर्ती करवाया गया है। इस वाहन में सवार अधिकतर यात्री पठानकोट पंजाब के रहने वाले हैं।

जन–धन

प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी है और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं व कमजोर समुदायों को सम्मान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना को वित्तीय समावेशन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया है।